RAJYA SABHA

Friday, the 13*th May*, 2005/23 *Vaisakha*, 1927 (*Saka*)

The House met at eleven of the clock

MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Agricultural Growth

*701. SHRI JESUDASU SEELAM†:
DR. T. SUBBARAMI REDDY:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether mid-term review of Tenth Five Year Plan has laid stress on revival of agricultural growth and rejuvenation of farm support system;

(b) if so, whether it has been pointed out that achieving the GDP growth rate of 8 per cent could critically depend on achieving higher growth rates in agriculture,

(c) if so, to what extent Government have considered the views expressed in the mid-term review;

(d) whether any concrete programme has been prepared by Government; and

(e) if so, the details thereof and to what extent it will be successful?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI KANTI LAL BHURIA): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Mid Term Appraisal (MTA) of the Tenth Five Year Plan has not yet been completed. It is, however, recognized that the satisfactory

---

† The Question was actually asked on the floor on the House by Shri Jesudasu Seelam.

performance of agriculture and allied sector is essential to achieving the Gross Domestic Product (GDP) growth rate of 8% per annum for the country as targeted under the Tenth Five Year Plan.

(d) and (e) The strategies formulated by the Government for making the agriculture sector more vibrant and dynamic so as to increase its production and productivity include (i) enhancing institutional credit flow to the farmers and strengthening of cooperative credit structure; (ii) ensuring the timely availability of quality inputs; (iii) promoting farmer friendly, demand driven agriculture extension system; (iv) accelerating diversification to high value crops including horticulture/activities; (v) strengthening infrastructure and the supply chain; (vi) optimizing the efficient utilization of available water resources through micro irrigation and enhancing the sustainability of dry-land/rainfed farming system; (vii) reforming agricultural markets, and widespread use of post harvest technology; and (viii) putting in place a broader spectrum of risk management apparatus for farmers.

SHRI JESUDASU SEELAM: Mr. Chairman, Sir, I would like to know, through, from the hon. Minister what is the specific role of the Central Government and what are the specific measures initiated by the Central Government as a result of the Mid-Term Appraisal. The Mid-Term Appraisal indicated, among other things, the share of agriculture in the overall GDP growth rate of eight per cent. The set target is four per cent, but if you look at the performance, it is coming less than four per cent in terms of its contribution to the GDP growth rate. The contribution of agriculture sector to the GDP fell from 24.7 per cent in 2001-02 to 20.5 per cent in 2004-05. In the light of this, what are the specific measures and the initiatives that the Central Government is going to take for increasing the contribution of the agriculture sector?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, उसमें दसवीं पंचवर्षीय योजना का मध्यावधि मूल्यांकन अभी पूरा नहीं हुआ है तथा यह माना जाता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार देश में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद विकास दर प्राप्त करने के लिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र में संतोषजनक कार्य-निष्पादन करना जरूरी है।

माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में 4 प्रतिशत विकास दर की बात कही है। जो विकास दर निर्धारित की गई है, अब तक 1.2 प्रतिशत कृषि विकास दर रही है,

इसके साथ ही कृषि में उत्पादन की जो दर कम हुई, उस मामले में भी माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है। माननीय सभापति जी, इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि-कृषि विकास दर कम होने का मुख्य कारण रहा हैं लगातार सूखे की स्थिति एवं कृषि विस्तार का कमजोर होना। तीसरे, कृषि विस्तार के कमजोर होने के कारण इसमें केन्द्र सरकार का जो रोल है, उसे सरकार कर रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24 प्रतिशत से भी ज्यादा हैं इस प्रश्न के उत्तर में माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रहीं हैं। व नई योजना भी प्रस्तावित है, ताकि विकास-दर बढ़ सके।

SHRI JESUDASU SEELAM: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister is aware that the irrigation facility is one of the important facilities through which we can improve the agricultural production, its productivity, and also its contribution to the GDP. I would like to know what are the specific measures and the initiatives that the Central Government is taking in areas where there is scanty rainfall or where there is monsoon failure, and especially in the dry areas of Andhra Pradesh, Northern Karnataka and Vidarbha region. This is number one. Number two; I would like to draw the attention of the hon. Minister to the remunerative price problems faced by the chilly growing farmers in Guntur and Prakasam Districts of Andhra Pradesh. There are people who are committing suicide. There are people who are burning their chilly crops. There is distress sale. There is a grave situation. I would like to draw the kind attention of the hon. Minister towards that.

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, वह वाजिब है और इसलिए सरकार ने पिछले साल का 2800 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2005-2006 के लिए 4800 करोड़ रुपए किया है। इसके साथ ही माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश की मिर्ची के बारे में जो चिंता जताई है, उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने आंध्र प्रदेश की पूरी तरह से मदद करने के लिए मन बनाया है और आंध्र प्रदेश सरकार जो भी प्रस्ताव भेजती है, उसको प्राथमिकता से करने का सरकार ने मन बनाया है। जो उन्होंने वहां की मिर्ची की बात कही है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 30,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई है। किसानों का मिर्ची का उत्पादन अधिक होने से वहां पर नाफेड के द्वारा यह खरीद की जा रही है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, कुल उत्पादन कितना है और उसमें से कितना आप खरीद रहे हैं?

श्री कांतिलाल भूरिया: सर, जो उन्होंने पूछा है, अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं माननीय सदस्य को वह जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, परन्तु वहां की जो स्थिति है, उससे अनुमति दी गई है

और 2700/–रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको भाव दे रहे हैं। गुंटूर के मामले में जो उन्होंने कहा है, मैं माननीय सदस्य को इस बारे में जानकारी अवश्य उपलब्ध करा दूंगा।

श्री जेसुदासु सीलम: सभापति जी, जो प्रस्ताव भेजे हैं, मंत्री महोदय ने कहा कि उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मैं स्पेसिफिक डिटेल जानना चाहता हूं कि कितने प्रस्ताव आए....?

श्री सभापति: नहीं, नहीं। आए बैठ जाइए। माननीय मंत्री महोदय, दो–तीन बार यह प्रश्न आ गया है। प्रश्न यह है कि मिर्ची का उत्पादन ज्यादा हुआ है और उसकी खरीद सरकार कम कर रही है और मार्केट में भाव कम मिल रहे हैं। इस समस्या का समाधान कैसे करना चाहते हैं? यह बताइए।

श्री कांतिलाल भूरिया: सभापति जी, जैसा मैंने निवेदन किया, आंध्र प्रदेश में मिर्ची का उत्पादन अधिक होने से मार्केट में कुछ भाव नीचे आ गया था और उस वजह से किसानों का जो उत्पादन हुआ, उसको उसकी कम कीमत न मिले, इसके लिए शासन ने एक सपोर्ट प्राइस डिसाइड करके और 2700/– रुपए देकर किसानों की 30,000 मीट्रिक टन मिर्ची खरीदी है, और भी आगे खरीदने के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं।

श्री सभापति: डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी। आपका प्रश्न मिर्ची से तो नहीं है? ....(व्यवधान)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: No, Sir. It is a good question which you will appreciate. In the Indian economy, the agricultural sector plays a very important role. As my friend has already said, it is going to contribute 4 per cent of the GDP. In this connection, the most important things are agricultural credit and providing water either rainwater or river water. I am extremely happy that the present Government has increased the agricultural credit from Rs. 37,000 crores to Rs.56,000 crores. As regards rain, States like Andhra Pradesh, Karnataka and other States have been reeling under drought for the last five years. What permanent and long-term measures are you contemplating to provide water facility, either by preserving rainwater or river water? What more activities are the Agriculture Ministry contemplating to increase agricultural production in the Indian economy?

MR. CHAIRMAN: This is practically a separate question. This is not concerned with this question.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, my question is whether the Mid-Term Review of the Tenth Five Year Plan has laid stress on revival of agricultural growth. The growth has been affected...*(Interruptions)*....

MR. CHAIRMAN: There are so many factors. ...(*Interruptions*)...

DR. T. SUBBARAMI REDDY: So, he has to give the reply. As per the Mid-Term Review of the Tenth Five Year Plan, he has to reply.

श्री सभापति: आपके पास इसका जवाब हो, तो दे दें।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य हमारे सीनियर हैं, काफी अनुभवी भी हैं और किसानों के काफी निकट भी हैं, इसलिए उनकी यह चिंता जायज है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को, कि हमारी यू॰पी॰ए॰ सरकार ने एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू किया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो आपने चिंता जाहिर की, ...(व्यवधान) ....सभापति महोदय, इसके लिए संविधान संशोधन किया जा रहा है ताकि वहां के किसानों को और उनको उनके द्वार तक जाकर कैसे मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही शुष्क क्षेत्र में शुष्क भूमि कृषि, बागवानी और शुष्क सिंचाई पर विशेष कार्यक्रम भी खेती के लिए उस क्षेत्र में कर रहे हैं और आयात के गिरते अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर भी किसानों को संरक्षण दिया जा रहा है, इसके साथ ही फसल बीमा करके भी किसानों को फायदा पहुंचाने की भी बात की जा रही हैं। आदान व आपूर्ति करने वाले संगठनों आदि के लिए भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे है। जहां तक पानी की बात है, वहां पर पानी की कमी है और वहां की राज्य सरकार जो भी प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी, केन्द्र सरकार निश्चित रूप से आगे होकर इस बात को देखेगी कि वहां के किसानों को हम लोग किस तरह से मदद कर सकते हैं।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, the answer says that the mid-term review is incomplete. When is the mid-term review likely to be completed? Since the Government has recognised that agriculture and allied sectors are very much essential for achieving the growth rate of 8 per cent, what steps have been contemplated for providing credit to small and marginal farmers, apart from the remunerative prices?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यू॰पी॰ए॰ सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सरकार ने जून, 2004 से व्यापक ऋण नीति की घोषणा की है और उसकी मुख्य बातें मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि कृषि ऋण प्रवाह तीन गुणा किया गया है, यू॰पी॰ए॰ सरकार से पहले 86 हजार करोड़ का ऋण प्रवाह था, उसको बढ़ाकर एक लाख पांच हजार....(व्यवधान)...

श्री सभापति: यह आप बता चुके हैं, आ चुका है हाउस में।

श्री कांतिलाल भूरिया: उसी तरह किसानों के बारे में पूछा है...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह बता चुके हैं, और कोई नई बात बतानी हो तो बताइए।

श्री दत्ता मेघे: चेयरमैन सर, मंत्री महोदय ने सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, मैं आपका और शरद पवार जी का स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या, खास तौर से विदर्भ में, कपास के बारे में है। वहां एकाधिकार खरीदी से किसानों को बहुत फायदा मिलता था। अभी इस साल हमने आपके पास प्रपोज़ल भेजा है, एक साल के लिए उन्होंने दे दिया। हम लोग केन्द्र सरकार की जो प्राइस थी, उससे ज्यादा कीमत देते थे। तो जो कीमत महाराष्ट्र सरकार कपास के उत्पादक को दे रही थी, वह कीमत आप देंगे क्या? विदर्भ में बड़े पैमाने पर आत्महत्याएं हो रही हैं, कपास की दरों के बारे में। तो जो एकाधिकार योजना थी, उसको चालू रखने के लिए केन्द्र सरकार पांच साल के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाने वाली है?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र के बारे में चिंता व्यक्त की है, वैसे भी महाराष्ट्र प्रदेश कपास का एक मुख्य उत्पादक प्रदेश माना जाता है और वहां पर काफी कपास का उत्पादन हुआ है। महाराष्ट्र सरकार दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा राशि बढ़ाकर खरीद करती है, इसलिए आसपास के दूसरे राज्यों के लोग भी वहां आकर अपना माल बेचना...(व्यवधान)....

श्री दत्ता मेघे: कपास की ज्यादा....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। आप बैठिए।...(व्यवधान)... यह गलत बात है। आप मंत्री जी को बोलने दीजिए। यह गलत बात है।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सदस्य, कपास की मांग की तुलना में उत्पादन ज्यादा हुआ है, यह हम मानते हैं। वहां किसानों को ज्यादा भाव मिल रहा है, लेकिन बाद में उस माल को जब मार्किट में ले जाया जाता है तो उसकी कीमत कम मिलती है, उसमें नुकसान होता है। माननीय सभापति जी, इसके लिए एन॰सी॰डी॰सी॰ से राशि देने की बात चल रही है ताकि उनकी खरीदी निरंतर चलती रहे और किसानों को परेशानी न हो। इनको सब्सिडी देने की एक नीति पर भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री सभापति: जल्दी कर दीजिए, जो कुछ करना है।

श्री वी॰ हनुमंत राव: चेयरमैन सर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाह रहा हूं कि गुंटूर में जो पिछले एक डेढ़ महीने से मिर्ची खरीदने की बात चल रही है, वह अभी तक कागजों पर ही चल रही है, खरीदने का काम कब शुरू करेंगे?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, गुंटूर के मामले में माननीय सदस्य ने जैसे बताया है, मैंने थोड़ी जानकारी दी है, फिर भी गुंटूर के मामले में अगर उन्हें डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, as per this Census, the Government has formulated eight strategies to increase agricultural production and thereby agricultural growth. Sir, I am on a different point, i.e. the cultivable land in India, though it is constant at 160 million hectares, in many States it is declining day-by-day. For example, in my State, half of the paddy fields have been converted into commercial purposes.

MR. CHAIRMAN: Don't give example. (*Interruptions*) Put your question.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN: So, my question is: Has the Government of India adopted any strategy to maintain the cultivable land in our country?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने ज़मीन जो कम होती जा रही है, इसके बारे में पूछा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन ज़मीन उतनी ही है और उस ज़मीन को बचाए रखने के लिए सरकार अपनी निगाह पूरी तरह से रखे हुए है, उन्हें हर प्रकार से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम लागू किए हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग निश्चित ही उन किसानों की मदद करेंगे। जितनी ज़मीन बंजर है, उसे भी हम तैयार करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी ज़मीन बनी रहे और हमारे किसानों को इस प्रकार की तक्लीफ न पहुंचे।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत गैर-सिंचित क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है और कितने बाढ़-प्रभावित क्षेत्र को बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा प्रस्तावित है? मान्यवर, मैं साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि आपने जो फ़सलों की खरीद की बात कही है, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में आपने कितने आलू की खरीद की?

श्री सभापति: मंत्री जी, बताइए। अब मिर्ची से आलू पर आ गए हैं, सावधान रहिए।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, जैसाकि मैंने पहले बताया कि सरकार सभी कैश क्रॉप के ऊपर पूरी तरह से ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, फिर चाहे वह आलू हो, टमाटर हो, मिर्ची हो, इसके साथ ही साथ फल-उद्यानों के माध्यम से भी हम इस बात को पूरी तरह से कर रहे हैं। जहां तक उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा गया है, तो मैं माननीय सदस्य को इस संबंध में अलग से जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस अनुपात में देश की आबादी बढ़ रही है, उस अनुपात में दसवीं पंचवर्षीय योजना में क्या हमारा

कृषि का उत्पादन उसके समकक्ष हो पाएगा? मैं यह इसलिए पूछना चाहता हूं क्योंकि दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों में, पिछले एक दशक में यह बात जानकारी में आई है कि कृषि का उत्पादन आबादी के अनुपात के अनुसार बढ़ नहीं रहा है, तो हमारी आबादी जो आज सौ करोड़ से अधिक की हो गई है, उस आबादी के लिए क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे के दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि का उत्पादन कितना होगा?

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, हमारे माननीय वरिष्ठ सदस्य ने ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्य बार-बार यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो इस प्रश्न को ही आप क्यों नहीं पूछते कि आबादी किस प्रकार से नहीं बढ़े?

श्री मोती लाल वोरा: इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, लेकिन उसके बाद भी आबादी निरन्तर बढ़ रही है, आबादी क्यों बढ़ रही है और उसकी आपूर्ति के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा कृषि का उत्पादन कितना हो पाएगा?

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the Minister of Health and Family Welfare is also here.

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, आबादी बढ़ने का जो प्रश्न है, वह हेल्थ विभाग के अन्तर्गत आता है। आबादी को रोकना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है, उसके साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में उत्पादन भी बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी यू॰पी॰ए॰ सरकार ने एक साझा कार्यक्रम बनाकर कई प्रकार के कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें हॉर्टीकल्चर एवं अन्य और भी कई प्रकार के कार्यक्रम हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, will this question continue for half-an-hour?

प्रो॰ राम देव भंडारी: माननीय सभापति जी, श्री तारिक साहब बैठे हुए हैं जो कटिहार से आते हैं। महोदय, बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों में जिसमें कटिहार भी है, जहां से तारिक साहब आते हैं, कटिहार, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, इन सब जिलों में मक्का की खेती बड़े पैमाने पर होती है आजकल स्थिति यह है कि मक्का हाई वे पर, खेत में, खलिहान में, हर जगह पड़ा हुआ है, उसे खरीदने वाला कोई नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो उसका मिनिमम प्राइज़, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह निर्धारित करें और दूसरा, ऐसी व्यवस्था की जाए कि सरकार के द्वारा उन किसानों से मक्का की खरीद की ली जाए।

श्री कांतिलाल भूरिया: माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्य ने इस बात के लिए चिंता जाहिर की है कि मक्का के मामले में तिलहन, दलहन, ऑयल पॉम और मक्का की योजना के तहत उन सबको मिलाकर एक योजना बनाई है और उसमें 240 करोड़ रुपए खर्च करके हम मक्का का क्षेत्र और बढ़ाएंगे और उनको किस तरह से मदद कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग विचार कर रहे हैं।

प्रो॰ राम देव भंडारी : खरीदने की भी व्यवस्था कीजिए।...(**व्यवधान**)

श्री कांतिलाल भूरिया: जो समर्थन मूल्य की बात कही है, वहां पर एक मूल्य आयोग बना हुआ है, वह पूरी स्थिति का जायजा लेता है और किसानों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करता है। ...(**व्यवधान**)... अब यू.पी.ए. सरकार ने फसल बोने से पहले सपोर्ट प्राइस डिकलेयर कर दी है। यह पहली बार ऐसा हुआ है। तो सरकार ...(**व्यवधान**)

प्रो॰ राम देव भंडारी : मक्का पड़ी हुई है उसका क्या होगा। ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति : भंडारी जी, छोड़िए, छोड़िए। आप दोनों ही बैठिए।

Meeting on Right to Food

*702. SHRIMATI VANGA GEETHA:†
SHRI RAMA MUNI REDDY SIRIGIREDDY:

Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal in favour of adopting a cross-sectoral approach for implementation of the right to food and treating it as multidimensional issue;

(b) if so, whether Government have called for any meeting in this regard recently;

(c) if so, the details of points discussed in the meeting; and

(d) the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (DR. AKHILESH PRASAD SINGH) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

---

†The question was actually asked on the floor of the House by Shrimati Vanga Geetha.